RAJYA SABHA

Friday, the 9th May, 1997/ 19 Vaisakha, 1919 (Saka)

The House met at eleven of the clock, The Deputy Chairman *in the Chair.*

श्रीमती कमला सिन्हा: मैडम, मुझे एक दरखास्त करनी थी आपसे और आपके माध्यम से हमारी सरकार को भी ।

उपसभापति : जी, बोलिए।

श्रीमती कमला सिन्हा: मैडम, इस देश को तो तरह तरह के मछरों ने चूसना शुरू ही किया हर इलाके में, लेकिन यहां सदन में हम बैठ नहीं सकते, इतना मछर हो गया चारों तरफ। मैं कल गई लाइब्रेरी में पढ़ने, मुश्किल हो गया बैठना और यहां भी हर रोज मछर काटते हैं। इसका कोई इलाज होगा या नहीं? दिल्ली शहर में डेंगू फीवर आ गया। **...(व्यवधान)...**

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे : पोलिटिकल कॉज है या नहीं ?

श्रीमती कमला सिंह : हां, उसका भी इन्वेस्टीगेशन हो जाए,पोलिटिकल कॉज है या नहीं ? स्कैम है या नहीं ? हैल्थ डिपार्टमेंट में कोई स्कैम है कि नहीं इसके लिए आप एक कमेटी बैठा दीजिए, जांच कराइए, लेकिन उसके पहले तत्काल हम लोगों को इससे त्राण दिलाइए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't know whether these mosquitoes were duly elected or not.

वही ड्यूली इलेक्टेड है, कि बगैर इलेक्शन के अंदर आ गए ।

SHRIMATI KAMLA SINHA: Whether they are elected or not, how can they intrude into the House?

SHRI SATISH AGARWAL: Madam, these mosquitoes were nominated by the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think ; I will ask the Secretariat to look into it.

मेरे पांव में भी काटते हैं ।

श्री मोहम्मद सलीम : जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना ज्यादा काटते हैं, **...(व्यवधान)...**

شری محمد سلیم: جتنے آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنے زیادہ کاٹتے ہیں..."مداخلت"...

उपसभापति : सबसे ज्यादा मच्छर चेयर के पास हैं ।

Now, Question No. 481.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Super Bazar Duped of Rs. 65 Lakh oa Wheat Deal

*481. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased.to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem captioned "Super Bazar duped of Rs. 65 lakh on wheat deal" which appeared in the "Hindustan Times", dated 26th April, 1997;

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto;

(c) persons responsible to give the contract to a mill located outside Delhi, which is against the rules; and

(d) the action taken or proposed to be taken against them?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) to (d) In view of the rising prices of wheat and Atta in the open market during 1996-97, Government introduced a scheme in July, 1996 of releasing wheat

[]Transliteration in Arabic script.
The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Jalaludin Ansari.

from Food Corporation of India to Super Bazar, Kendriya Bhandar and National Co-operative Consumers' Federation of India Ltd. (NCCF), to sell the resultant Atta at prices fixed by Government. According to Super Bazar, it was allotted 24,700 tonnes of wheat upto March, 1997. Of the several Mills engaged for this purpose by the Gaper Bazar, M/s Etawah Hour Mills, Etawah (UP) offered cheaper rate of conversion of wheat into Atta. The mill was allotted 2000 MT ot wheat in March, 1997 by the Purchase Committee as per rules. The mill also deposited Rs. One Crore to FCI by Demand Draft and actually lifted 1149.5 tonnes of wheat.

M/s Etawah Flour Mills delivered some quantity of atta, though belatedly, but the same was not accepted by Super Bazar due to poor quality.

A team of officials of Super Bazar had visited Etawah Flour Mills in the last week of April, 1997 to go into the details and the reasons for non delivery of Atta and wheat lifted by the mill.

A notice has been served on M/s Etawah Flour Mills as to why the advance lying with FCI/Super Bazar should not be forfeited being the difference of amount between the FCI rates and market rates.

The Central Registrar of Cooperative Societies has been asked to conduct an Enquiry into the matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It has been brought to my notice that there are some questions which are related to wheat. We will put them together. तो जिनके नाम उसमें हैं, उनको उसके साथ में बुला लेंगे ।

SHRI K.R. MALKANI: There are four Questions, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I know. We will discuss them together.

जी, सप्लीमेंटरी ।

श्री जलालुद्दीन अंसारी : उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा नियम था, अपने उत्तर में इन्होंने बताया है कि दिल्ली में आटे की कमी और महंगाई के कारण भारतीय खाद्य निगम से सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार तथा राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड को गेहूं देने की एक स्कीम शुरू की गई थी ताकि निवमत मूल्यों पर आटे की बिक्री की जा सके, सही दाम पर । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले अगर यह नियम था कि दिल्ली के अंदर ही फ्लोर मिल्स को पिसाई के लिए गेहूं दिया जाए तो किन अधिकारियों ने इस नियम को तोड़ते हुए इटावा मिल्स को यहा दिया, 24,700 टन गेंहूं और उसने जो पीस कर दिया भी तो वह रद्दी आटा दिया, खाने लायक आटा नहीं दिया। इस संबंध में उनके खिलाफ कौनसी कार्यवाही की जा रही है? मैं सबसे पहले इसी बात को जानना चाहूंगा और ऐसा क्यों किया गया, यह जानना चाहूंगा।

شری جلال الدین انصاری: اپ سبھاپتی مہودے۔ میں مانیہ منتری مہودے سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا اصول تھا۔ اپنے جواب میں انھوں نے بتایا ہے کہ دلی میں آٹے کی کمی اور مہنگائی کے کارن "بھارتیہ کھادے نگم" سے سپربازار۔کیندریہ بھنڈار اور راشٹریہ سہکاری سنگھ لمیٹیڈ کو گیہوں دینے کی ایک اسکیم شروع کی گئی تھی تاکہ طے قیمتوں پر آٹے کی بکری کی جا سکے۔ صحیح دام پر تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پہلے اگر یہ اصول تھا کہ دلی کے اندر ہی فلور مل کو پیسائی کیلئے گیہوں دیا جائے تو کن افسروں نے ان اصولوں کو توڑتے ہوئے اٹا واملس کو یہ دیا ۲۴،۷۰۰ ٹن گہیوں اور اسنے جو پیس کر دیا بھی تو وہ ردی آٹا دیا۔ کھانے لائق آٹا نہیں دیا۔ اس سلسلے میں انکے خلاف کونسی کارروائی

[] Transliteration in Arabic Script.

کی جا رہی ہے۔ میں سب سے پہلے اسی بات کو جاننا چاہونگا۔اور ایساکیوں کیاگیا یہ جاننا چاہونگا۔

श्री चतुरानन मिश्र : उप्सभापति महोदया, ऐसी बात है कि यह तो कोपरेटिव है, माल्टी स्टेट स्टेट कोपरेटिव। आटा या दूसरा काम यह कहीं से भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रक्शन है इस पर, वह बात नहीं है और इसलिए इस तरह का रूल नहीं है। वैसे मैं माननी सदस्य को धन्यवाद देता हूं कीन्होंने इस करप्शन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हमने, जैसा आपसे कहा कि, रजिस्ट्रार आफ कोपरेटिव्स को इसकी जांच के लिए दे दिया है, जो एडीशनल इस संबंध में भी जांच करेंगे और आपने प्रिडर्स नोटिस दे दिया है केस करने के लिए उस पर। इसके अतिरिक्त हमने कल उनसे कहा है कि इसमें ब्रीच आफ ट्रस्ट का केस बनता है या नहीं, यह लीगल ओपिनियन ले लें और उसके मुताबिक काम करें।

श्री जलालुदीन अंसारी : महोदय, मंत्री जी ने स्वीकारा है कि यह ब्रीच आफ ट्रस्ट का केस बनता है और उन्होंने अ भी कहा है कि उसकी जांच के लिए आदेश भी दिया गया है। साथ ही साथ अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक से मामले की जांच कराने के लिए भी कहा गया है। मेरा यह सुझाव होगा कि अगर यह मामला ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बनता है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ जिन अधिकारियों ने ठेका उनको दिया, उनसे भी यह तलब किया जाना चाहिए कि किस परिस्थिति में उन्होंने उस मिल को ठेका दिया,जिसने घटिया किसम का आटा दिया, वह भी पूरा नहीं दिया ? इससे लगता ऐसा है कि इसके पीछे कुछ अधिकारियों और फ्लोर मिल के बीच कुछ गड़बडी का मामला निश्चित तौर पर है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो संबंधित अधिकारी इसके लिए दोषी पाए जाएं, उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

شری جلال الدین انصاری: مہودے منتری جی نے سویکار کیا ہے کہ یہ "بریچ آف ٹرسٹ کا کیس بنتا ہے اور انھوں نے ابھی کہا ہے کہ اسکی جانچ کیلئے آدیش بھی دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے جواب میں انھوں نے کہا ہے کہ سرکاری سمیتیوں کے کیندریہ پنجبیک سے معاملے کی جانچ کرانے کیلئے بھی کہا گیا ہے۔ میرا یہ سوجھاؤں ہوگا کی اگر یہ معاملہ "بریچ آف ٹرسٹ" کا بنتا ہے تو اس پر سخت کاروائی کی جانی چاہئے۔ ساتھ ہی ساتھ جن افسروں نے ٹھیکا انکو دیا ، ان سے بھی یہ طلب کیا جانا چاہئے۔ لیکن حالات میں انھوں نے اس مل کو ٹھیکہ دیا جسنے گھٹیا قسم کا آٹا دیا اور وہ بھی پورا نہیں دیا۔ اسسے لگتا ایسا ہے کہ اسکے پیچھے کچھ ادھیکاریوں اور فلور ملس کے بیچ کچھ گڑبڑی کا معاملہ یقینی طور پر ہے تو اسکی بھی جانچ ہونی چاہئے اور جو متعلقہ ادھیکاری اسکے لئے دوشی پائے جایئں انکے خلاف بھی ضروری کاروائی کی جانی چاہئے۔

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है, अब यह तो हम नहीं कह देंगे कि कार्रवाई कर देंगे, जब रिपोर्ट आ जाएगी, वे दोषी साबित होंगे तो जरूर ही कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रार ऑफ दि ट्रेड यूनियन्स से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए हमने लीगल ओपीनियन मांगा है, ज्यों ही जाएगा, उसके मुताबिक काम करेंगे।

उपसभापति : एक्कुअलो मैंने जो क्लब भी करे हैं,

those Members are not present. Mr Gurudas Das Gupta is not there. Dr. Y. Lakshmi Prasad is not there. Mr. Satish Pradhan is not there. Mr. Vayalar Ravi is

[] Transliteration in Arabic Script.

not there. Mr. S.M. Krishna is not there. So, my clubbing them has not resulted fruitfully. Those questions have been clubbed and are being taken up...

SHRI G. SWAMINATHAN: That may be the reason why all the people are away.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने बहुत सही कहा कि वे जांच कर रहे है और जांच के अनुकूल जो परिणाम आएगा, उस पर वे कदम उठाएंगे । जन-स्वास्थ्य का मामला है और इसके ऊपर भी अगर कोई कालाबाजारी करता है या कोई मिलावट करता है तो केवल वही अपराधी नहीं है, जिस मिल में यह अपराध हुआ है, मैं मानता हूं कि वे लोग भी अपराधी हैं जिन्होंने उनका नाम सुझाया है और इतने बडे परिमाण में गेहूं वहां भेजा गया है, उन आदमियों की भी जांच-पड़ताल होनी चाहिए ।

श्री चतुरानन मिश्र : जांच-पड़ताल तो सभी चीज़ की होगी, लेकिन जो परिस्थिति थी वह यह थी कि दिल्ली के मिल-मालिक ज्यादा पैसा चाहते हैं-1.40 रुपया प्रति किलो आटा पिसने के लिए, जिस मिल को ठेका दिया गया है, उसने 1.25 रुपया आफर दिया । जब इस तरह की चीज़ होती है कि ज्यादा काम सरकार करने लगती है तो ट्रेड ऐसा रास्ता अख्तियार करता है जो जनता के हित में नहीं है । इसलिए हमने सदन को कई बार कहा है कि सरकार तो ट्रेड का फ्रेंडली है लेकिन ट्रेड सरकार का फ्रेंडली नहीं है । इस पर सदन सोचे तो कुछ आगे की कार्रवाई चले । लेकिन हम आपकी बात से सहमत हैं कि जो जांच हो, वह सर्वांगीण होनी चाहिए ...(**व्यवधान**)...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : वह दंडित होना चाहिए । अपराधी जब तक दंडित नहीं होगा, तब तक अपराध बढ़ते जाएंगे । अपराध अगर हुआ हो तो दंडित होना चाहिए ।

श्री चतुरानन मिश्र : अभी अगर हम कह देंगे कि दंडित होगा तो कोर्ट कह देगा कि यह तो पहले ही तय कर लिए हैं । इसलिए हम तब कहेंगे जब रिपोर्ट आ जाएगी, उसकी जांच हो जाएगी नहीं तो दूसरे लोग हमको पकडेंगे कि यह तो प्री डिटरमिंड है, जजमेंट ।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : ठीक है, वह मैं मानता हूं ।

श्री बंगारू लक्ष्मण : उपसभापति जी, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि मिलों को गेहूं देने के कारण मिल आटा बनाने के लिए चार्जिस बहुत लगा रही हैं, जिसका अल्टींमेटली कंज्यूमर पर भार पड़ रहा है । फिर कुछ ऐसे बल्क कंज्यूमर भी हैं, जैसे छोटे-छोटे बिस्कुट मेन्युफेक्चर्स हैं, बेकरी वाले हैं, ब्रेड मेन्युफ्क्चर्स हैं, इनकी भी आवश्यकता होती है और फूड कारपोरेशन ने या सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने भी उनको मिल से खरीद कर्ने के लिए कहा है, जिसके कारण उन्हें ज्यादा दाम देने पड़ते हैं और जितनी मात्रा में उन्हें सामान चाहिए होता है, वह मिल नहीं पा रहा है। क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि यह जो स्माल स्केल इडस्ट्री में हमारी जो यह बेकरी या बिस्कुट वगैरह की इंडस्ट्री है, इनको फूड कारपोरेशन से सीधा दिया जा सके, क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी? में आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आंध्रा प्रदेश में बिस्कुट बनाने की बहुत बडी इंडस्ट्री है। वहां ऐसी 5,000 यूनिटस सारे प्रदेश में काम कर रही हैं और हजारों की संख्या में मजदूर उनमेम काम कर रहे हैं। अब चूंकि मिल के द्वारा गेहूं लेने की बात है और मिल अपनी मरजी से बेचती है, इसलिए उनको गेहूं नही मिल रहा है और कई बिस्कुट फैक्ट्रियां बंद पडी हैं। क्या सरकार इन बिस्कुट मैंयुफैक्चरर्स को एफ.सी.आई. के द्वारा कोटा देने का प्रबंध करेगी?

श्री चतुरानन मिश्र: उपसभापति महोदया, अगर कंक्रीटली मलूम हो कि किसको गेहूं नहीं मिल रहा है तो हम जो कोटा देते हैं आंध्र प्रदेश को, उसमें हम कहेंगे कि इनको भी दे दो। हम छोटे मैन्युफैक्चरर्स के पक्ष में हैं लेकिन जब हम छोटे निर्माताओं को गेहूं पीसने के लिए देते हैं तो वे घुन भी पीस देते हैं। वैसे हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास गेहूं का स्टॉक है। आप आंध्र प्रदेश सरकार से उसकी रिक्विजिशन भिजवा दीजिए, हम उनको पूरा कर देंगे।

SHRI J. CHITRANJAN: Madam Chairperson, wheat is allotted to mills, super markets and other agencies. I want to know whether there is any permanent set-up to monitor as to how this wheat is utilised, whether there is any pilferage or it is diverted for some other purposes. The hon. Minister may kindly give information about that.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Madam, we give it to the State Governments as per their quota. As far as taking up further monitoring is concerned, it is for the State Government to do it. Broadly, we look into the matter.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: महोदया, 3 साल पहले उस वक्त की सरकार ने एक प्रोग्राम किया था मॉडर्न बेकरीज़ के थ्रू, ताकि सस्ते दाम में गरीब लोगों को ब्रेड मिल जाए। उसके पब्लिक फंक्शंस दिल्ली और बंबई में किए गए थे और उन्होंने यह मूवमेंट प्राइवेट वेकरीज तक पहुंचाने की कोशिश कि थी। अब यह मालूम हो रहा है कि उस सरकार ने जो यह स्कीम गरीबों के लिए चालू की थी, एफ.सी.आई. उनको गेहूं नही दे रही है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। जो मैंन्युफैक्चरर्स ब्रेड बनाते हैं, उनको गेहूं नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको ब्लैक मार्केट से लेना पड़ता है, इसलिए कीमतें बढ़ गई हैं और गरीबों को उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने कुछ डॉयरेक्शन दी है एफ.सी.आई. को कि गरीबों के लिए जो मैंयुफैक्चरर्स ब्रेड बनाते हैं, उनको प्रॉयोरिटी पर गेहूं दिया जाय? क्या इस दिशा में कुछ प्रयास आप कर रहे हैं? हमारी जानकारी यह है कि उनको गेहूं नहीं मिल रहा है। तो गरीबों के लिए सरकार की जो यह स्कीम थी, उसके बारे में यदि आप प्रकाश डालें तो देश के गरीबों को कुछ फायदा हो जाएगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I wonder which bakeries make bread for the *garib.*

गरीब को तो सूखी रोटी नहीं मिलती है ।

SHRI SUSHILKJMAP SAMBHAJIRAO SHINDE: Madam, I would like to mention here that during the Prime Ministership of Shri, P.V. Narasimha Rao, out of two places in Delhi, I was present in one of the opening ceremonies in which bread was given at a very low price.

श्री एन.के.पी. साल्वे : मैडम पाव तो खाते हैं बंबई में ।

श्री चतुरानन मिश्र : एक तो उन्होंने एक खास कम्पनी मॉडर्न वेकरीज के बारे में कह, वह तो हम जांच करवा लेंगे तभी आपको कुछ बता सकते हैं कि ऐसा है या नहीं। अगर ब्रेड बनाते हैं तो यह लिखा नहीं रहेगा कि गरीब ही खाएं। जिसको खाना है खाए। हम तो गेहूं दे देंगे उनके नाम पर और वह ब्रेड बनएंगे।

श्री एन.के.पी. साल्वे : मंत्री महोदय की भाषा कुछ बदल रही है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे : रईस की ब्रेड अलग होती है, छोटे लोगों की ब्रेड अलग होती है, पाव होती है।

श्री एन.के.पी. साल्वे : पाव होता है बंबई में, गरीब से गरीब आदमी उसको खाता है।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने कहा कि एक बार जब हम उनको गेहूं दे देगे तो गरीब खाए या अमीर खाए, यह तो उनके हाथ में रहेगा। हम देखेंगे कि अगर उनको गेहूं नहं मिलता है तो उसके लिए क्या किया जाए ।

Establishment of Village/ Libraries

*482. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Department of culture had a proposal to begin from 1995-96 for setting up of Village Libraries with basic educational facilities; and

(b) if so, the reason as to why the proposal did not become a reality and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHIRAM SAIKIA): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal for School-cum-Village Library Scheme was not approved by Minsitry of Finance, which advised the evaluation of the existing schemes to avoid duplication.

An indepth evaluation of the schemes was undertaken and the scheme modified in the light of the 73rd and 74th Amendment of the Cratitution, whereby the Zila Parishad and the Panchayat Samities have been designated as the nodal agencies to offer Lbrary services at the rural level. Hence a scheme known as "the scheme of Financial Assistance for Setting up of Rural Libraries" has been